Daily Current Affairs
31 July 2025

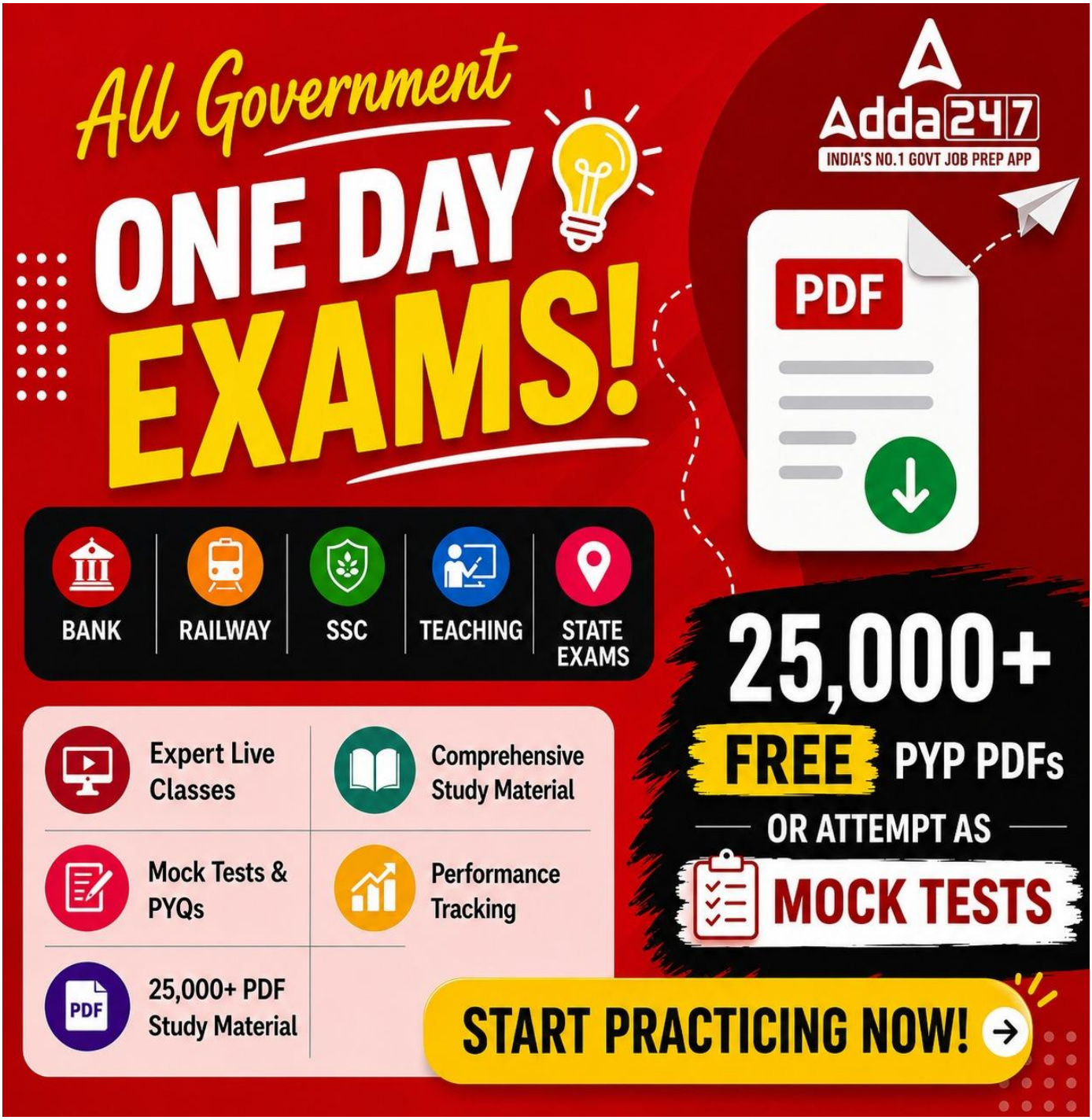

Daily Current Affairs Quiz 31 July 2026

Q1. कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक परियोजना की अनुमानित शेष लागत है:

(a) 5,143.22 करोड़ रुपये

(b) 6,282.32 करोड़ रुपये

(c) 6,143.22 करोड़ रुपये

(d) 7,143.22 करोड़ रुपये

Ans.(c)

Sol. सही उत्तर (C) 6,143.22 करोड़ रुपये है

स्पष्टीकरण:

• आधिकारिक सरकारी स्वीकृतियों और परियोजना मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, बिहार में कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक परियोजना के निष्पादन के लिए अनुमानित शेष लागत 6,143.22 करोड़ रुपये है।

• प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए स्वीकृत वित्त पोषण संरचना के तहत, केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में 60% वित्तीय घटक प्रदान करती है, जबकि शेष 40% राज्य का हिस्सा बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

• इस पर्याप्त वित्तीय आवंटन में भूमि अधिग्रहण, नहर आधुनिकीकरण, क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं का निर्माण, पुलों, हेडवर्क्स और पर्यावरणीय न्यूनीकरण उपायों सहित प्रमुख पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

• 6,143.22 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी राज्य जल संसाधन विभाग को निविदाओं को व्यवस्थित रूप से निष्पादित करने और नहर मार्ग के विस्तार के लिए मिट्टी के काम को तेज करने की अनुमति देती है।

• इस पूंजी के निवेश से कृषि आजीविका को सुरक्षित करने, फसल की पैदावार बढ़ाने और पूर्वी बिहार में वार्षिक बाढ़ से होने वाले नुकसान की लागत को भारी रूप से कम करके अपार आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

Information Booster:

• प्रमुख जल अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की संशोधित लागत समिति के माध्यम से प्रदान की जाती है।

• केंद्रीय वित्त पोषण ढांचे के तहत कोसी-मेची परियोजना को शामिल करने से वित्तीय स्थिरता मिलती है और राज्य सरकार के लिए स्थानीय वित्त पोषण की बाधाएं समाप्त होती हैं।

• परियोजना के लिए आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (EIRR) अध्ययन फसल की सघनता और आपदा की रोकथाम के कारण पूंजीगत परिव्यय से कहीं अधिक दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हैं।

• प्रभावित भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पैकेज कुल अनुमानित परियोजना लागत का एक अनिवार्य प्रतिशत है।

• यह परियोजना प्रत्यक्ष निर्माण नौकरियों और अप्रत्यक्ष कृषि उत्पादकता लाभों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण रोजगार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी।

Additional Knowledge:

• 5,143.22 करोड़ रुपये (विकल्प A): मुद्रास्फीति समायोजन और उन्नत पर्यावरण अनुपालन लागतों को शामिल करने से पहले प्रारंभिक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान तैयार किए गए प्रारंभिक लागत अनुमान का प्रतिनिधित्व करता है।

• 6,282.32 करोड़ रुपये (विकल्प B): बाद के राज्य चरण के विकास के तहत नियोजित द्वितीयक कमान क्षेत्र नहर नेटवर्क विस्तार सहित कुल संयुक्त अनुमानित परिव्यय को संदर्भित करता है।

• 7,143.22 करोड़ रुपये (विकल्प D): बहु-दशक निर्माण-पश्चात जीवनचक्र में संभावित दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव व्यय के लिए अनुमानित एक बढ़ा हुआ अनुमान।

Q2. बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नदी पर बांध निर्माण की चर्चाओं से कौन सा पड़ोसी देश जुड़ा है?
(a) भूटान
(b) बांग्लादेश
(c) चीन
(d) नेपाल
Ans.(d)
Sol. सही उत्तर (D) नेपाल है
स्पष्टीकरण:
• नेपाल भारत का तत्काल उत्तरी पड़ोसी देश है जिसके साथ प्रस्तावित सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सुन कोसी भंडारण सह व्यपवर्तन योजना के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त तकनीकी अध्ययन किए गए हैं।
• तिब्बत (चीन) के उच्च हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली और भारतीय राज्य बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल से होकर बहने वाली कोसी नदी, अपनी गंभीर आवर्ती वार्षिक बाढ़ और बार-बार मार्ग बदलने के कारण 'बिहार का शोक' के रूप में व्यापक रूप से कुख्यात है।
• उत्तरी बिहार के जिलों और नेपाल के निचले क्षेत्रों में बाढ़ के विनाशकारी जलप्लावन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, दोनों राष्ट्र नेपाल के बराहक्षेत्र में एक विशाल बहुउद्देशीय भंडारण बांध के निर्माण के लिए विस्तृत जांच करने पर सहमत हुए।
• प्रस्तावित कोसी उच्च बांध का उद्देश्य नेपाल और भारत दोनों में कृषि भूमि के विशाल इलाकों में सिंचाई कवरेज, जलविद्युत के माध्यम से बिजली उत्पादन, और उन्नत अंतर्देशीय नेविगेशन मार्गों सहित कई अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) लाभ प्रदान करना है।
• जल संसाधनों पर भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग ऐतिहासिक संधियों और संस्थागत तंत्रों द्वारा शासित होता है, जिसमें कोसी और गंडक परियोजनाओं को समर्पित जल संसाधन पर संयुक्त समिति (JCWR) और विशेषज्ञों का संयुक्त दल (JTE) शामिल हैं।
Information Booster:
• कोसी नदी पूर्वी नेपाल में सात प्रमुख पहाड़ी सहायक नदियों के संगम से बनने वाली एक सीमा-पार नदी है, जिसे सामूहिक रूप से सप्तकोसी (जिसमें सुन कोसी, अरुण और तमोर नदियां शामिल हैं) के रूप में जाना जाता है।
• भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण, अप्रैल 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक कोसी समझौते के बाद किया गया था।
• भारी गाद भार और उच्च तलछट परिवहन कोसी नदी की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो नदी के तल की ऊंचाई में तेजी से वृद्धि करती हैं और पिछले दो शताब्दियों में बड़े पैमाने पर एवल्शन (अचानक मार्ग परिवर्तन) का कारण बनी हैं।
• ऊपर के नेपाली जलग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन और भंडारण जलाशय निर्माण को बाढ़ के चरम निर्वहन को नियंत्रित करने के लिए सबसे टिकाऊ दीर्घकालिक इंजीनियरिंग समाधान माना जाता है।
• भारत और नेपाल 250 से अधिक नदियां साझा करते हैं, जिनमें क्षेत्रीय जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण महाकाली (शारदा), कर्णाली (घाघरा), गंडक और कोसी प्रणाली जैसे प्रमुख सामान्य बेसिन शामिल हैं।
Additional Knowledge:
• भूटान (विकल्प A): भारत प्रमुख रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं जैसे कि ताला, चूखा, कूरीछू और पुनात्सांगछू पर भूटान के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करता है, लेकिन भूटान कोसी नदी प्रणाली से जुड़ा नहीं है।
• बांग्लादेश (विकल्प B): भारत संयुक्त नदी आयोग (JRC) के माध्यम से बांग्लादेश के साथ निचले तटवर्ती जल प्रबंधन संवाद साझा करता है, जिसमें गंगा और तीस्ता सहित 54 साझा नदियां शामिल हैं, लेकिन कोसी नदी नहीं।

• चीन (विकल्प C): यारलुंग जांगबो (ब्रह्मपुत्र) और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र) में स्थित हैं, जहां डेटा-साझाकरण समझौते मौजूद हैं, लेकिन कोसी बाढ़ नियंत्रण के लिए सक्रिय संयुक्त बांध निर्माण संवाद नेपाल पर ही केंद्रित हैं।

Q3. मेची नदी किस नदी बेसिन का हिस्सा है?

(a) ब्रह्मपुत्र बेसिन

(b) यमुना बेसिन

(c) गोदावरी बेसिन

(d) महानंदा बेसिन

Ans.(d)

Sol. सही उत्तर (D) महानंदा बेसिन है

स्पष्टीकरण:

• मेची नदी एक सीमा-पार नदी है जो नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती है, भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बहती है, और बड़े महानंदा नदी बेसिन का एक अभिन्न अंग बनाती है।

• पूर्वी नेपाल और भारत में पश्चिम बंगाल/बिहार के पहाड़ी इलाकों और मैदानों से होकर गुजरने के बाद, मेची नदी महानंदा नदी में मिल जाती है, जिससे यह महानंदा की प्रत्यक्ष सहायक नदी बन जाती है।

• महानंदा नदी प्रणाली स्वयं गंगा नदी की एक प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी है, जो गंगा में शामिल होने से पहले नेपाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से जल निकासी करती है।

• कोसी-मेची लिंक परियोजना महानंदा बेसिन के भीतर कोसी बेसिन से अतिरिक्त पानी को मेची नदी में स्थानांतरित करती है, जिससे महानंदा बेसिन कमान क्षेत्र में मौसमी पानी की कमी दूर होती है।

• महानंदा बेसिन के भीतर मेची नदी की भौगोलिक स्थिति इसे बिहार के जल-अभाव वाले पूर्वी जिलों की सिंचाई के लिए कोसी के अतिरिक्त पानी को मोड़ने के लिए आदर्श अंत-बिंदु बनाती है।

Information Booster:

• मेची नदी पूर्वी नेपाल (झापा जिला) को पूर्वी भारत (पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और बिहार के किशनगंज जिले) से अलग करने वाली एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा बनाती है।

• महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में कुर्सियोंग के पास चिमली में दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरी पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है।

• महानंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मेची, बालासन, रटवा, कंकाई और नागर नदियां शामिल हैं।

• कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक में कोई विदेशी भूमि हस्तांतरण या संधि पुनर्विचार शामिल नहीं है क्योंकि मेची से मिलने से पहले यह मोड़ पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर होता है।

• महानंदा बेसिन घनी ग्रामीण आबादी, सघन कृषि भूमि उपयोग और मानसूनी बाढ़ के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ के प्रति उच्च भेद्यता की विशेषता है।

Additional Knowledge:

• ब्रह्मपुत्र बेसिन (विकल्प A): महानंदा प्रणाली के पूर्व में स्थित एक विशाल अंतरराष्ट्रीय नदी बेसिन, जो तिब्बत, पूर्वोत्तर भारत (असम, अरुणाचल प्रदेश) और बांग्लादेश से जल निकासी करती है, कोसी-मेची हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क से अलग है।

• यमुना बेसिन (विकल्प B): गंगा की सबसे बड़ी सहायक बेसिन, जो बिहार के बहुत पश्चिम में स्थित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित उत्तरी और मध्य राज्यों से जल निकासी करती है।

• गोदावरी बेसिन (विकल्प C): भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बेसिन, जो महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है।

Q4. कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि है:
(a) मार्च 2028
(b) मार्च 2030
(c) दिसंबर 2028
(d) मार्च 2029
Ans.(d)
Sol. सही उत्तर (D) मार्च 2029 है
स्पष्टीकरण:
• बिहार राज्य में एक ऐतिहासिक नदी जोड़ो पहल, कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2029 निर्धारित किया गया है।
• इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक विस्तारित मुख्य नहर प्रणाली के माध्यम से कोसी नदी बेसिन से अतिरिक्त पानी को जल-अभाव वाले मेची नदी बेसिन (महानंदा नदी की एक सहायक नदी) की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है।
• मार्च 2029 की समय-सीमा का पालन करने का प्राथमिक उद्देश्य बिहार के सीमांचल क्षेत्र में, विशेष रूप से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को शामिल करते हुए विस्तृत कृषि क्षेत्रों को तत्काल गारंटीकृत सिंचाई जल आपूर्ति प्रदान करना है।
• राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ बिहार के जल संसाधन विभाग की देखरेख में क्रियान्वित, निष्पादन कार्यों में नहर चौड़ीकरण, संरचना निर्माण और पर्यावरणीय मंजूरी शामिल हैं।
• मार्च 2029 के लक्ष्य को पूरा करने से पूर्वी कोसी बेसिन में बाढ़ के खतरे काफी कम हो जाएंगे और साथ ही वर्षा आधारित कृषि भूमि अत्यधिक उत्पादक दोहरे फसल वाले कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाएगी।
Information Booster:
• मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली ऐतिहासिक केन-बेतवा लिंक परियोजना के बाद, केंद्रीय वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने वाली कोसी-मेची लिंक भारत में दूसरी प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है।
• यह परियोजना मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (EKMC) प्रणाली का उपयोग करती है, जिसे फिर से तैयार किया जाएगा और मेची नदी तक लगभग 76 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा।
• पूरा होने पर, यह परियोजना बिहार के चार पूर्वी जिलों में 2.14 लाख हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
• भारत में नदी जोड़ो परियोजना की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) द्वारा की जाती है।
• संपूर्ण परियोजना वास्तुकला गुरुत्वाकर्षण प्रवाह डिजाइन पर निर्भर करती है, जिससे उच्च लागत वाली बिजली-गहन जल उत्थापन योजनाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
Additional Knowledge:
• मार्च 2028 (विकल्प A): प्रारंभिक सिविल संरचनाओं के लिए एक पूर्व अस्थायी आंतरिक चरण की समयरेखा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन पूर्ण कमीशन के लिए आधिकारिक स्वीकृत अंतिम पूर्णता समय सीमा का गठन नहीं करता है।

• मार्च 2030 (विकल्प B): मुख्य नहर लिंक निर्माण पूरा होने की तारीख के बजाय द्वितीयक कमान क्षेत्र विकास और फील्ड चैनल वितरण नेटवर्क के लिए विस्तारित दीर्घकालिक लक्ष्य अनुमानों को संदर्भित करता है।
• दिसंबर 2028 (विकल्प C): अंतिम कमीशनिंग से पहले मुख्य नहर ट्रंक लाइन के साथ प्राथमिक मिट्टी तटबंध सुदृढीकरण को पूरा करने के लिए निर्धारित एक मध्यावधि परिचालन मील का पत्थर लक्ष्य।

Q5. केंद्र सरकार ने कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक परियोजना को किस योजना के तहत मंजूरी दी?
(a) अटल भूजल योजना
(b) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
(c) जल जीवन मिशन
(d) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
Ans.(b)
Sol. सही उत्तर (B) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है
स्पष्टीकरण:
• भारत की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) ढांचे के तहत कोसी-मेची अंतः-राज्यीय लिंक परियोजना के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की।
• PMKSY-AIBP के तहत शामिल होने से इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता वाली राष्ट्रीय सिंचाई और नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए निर्धारित आवश्यक केंद्रीय वित्तीय सहायता (60% केंद्रीय हिस्सा) सुरक्षित करने में मदद मिलती है।
• PMKSY-AIBP घटक विशेष रूप से कृषि योग्य कमान क्षेत्रों का विस्तार करने और खेत-स्तर पर जल दक्षता बढ़ाने के लिए प्रमुख और मध्यम सिंचाई कार्यों को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखता है।
• कोसी-मेची लिंक को इस प्रमुख छत्र योजना (अम्ब्रेला योजना) में शामिल करके, केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा कार्यों का व्यवस्थित वित्त पोषण प्रवाह, कठोर निगरानी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करती है।
• यह योजना 'हर खेत को पानी' (हर खेत के लिए पानी) के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार के अनुरूप है।
Information Booster:
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को 2015 में 'हर खेत को पानी' और 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' के आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया था।
• PMKSY चार प्रमुख घटकों को एकीकृत करता है: AIBP (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम), हर खेत को पानी (HKKP), पर ड्रॉप मोर क्रॉप (सूक्ष्म सिंचाई), और वाटरशेड विकास।
• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) मूल रूप से 1996-97 में राज्यों को चल रही अधूरी प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
• कोसी-मेची लिंक अद्वितीय है क्योंकि यह केंद्रीय PMKSY-AIBP समर्थन के तहत वित्त पोषित अग्रणी अंतः-राज्यीय नदी जोड़ो योजनाओं में से एक है।
• जल शक्ति मंत्रालय, जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विलय से 2019 में बनाया गया था, PMKSY के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
Additional Knowledge:
• अटल भूजल योजना (विकल्प A): एक विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो मुख्य रूप से सात भारतीय राज्यों में जल-संकट वाले क्षेत्रों में टिकाऊ भूजल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है, न कि प्रमुख नदी लिंक नहरों पर।

• जल जीवन मिशन (विकल्प C): ग्रामीण पेयजल सुरक्षा को बढ़ावा देकर भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में सुरक्षित पेयजल के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रमुख केंद्रीय पहल।
• राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (विकल्प D): नहर सिंचाई परियोजनाओं के बजाय, अवरोधन, मोड़ और सीवेज उपचार संयंत्र (STP) निर्माण के माध्यम से प्रदूषित नदी खंडों में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित एक केंद्रीय योजना।